



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 200] नई दिल्ली, शुक्रवार, विसंवर 15, 1967/ग्रहायण 24, 1889

No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1967/AGRAHAYANA 24, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संक्षेप से रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 15th December 1967

No. 16(5)Plant(B)/67.—In Government's letter No. 16(2)Plant(B)/65 dated the 28th October, 1966, the Tariff Commission was requested under section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to conduct necessary enquiries in regard to the cost of production of raw rubber and to submit a report on the fair prices for its different grades and qualities. The Commission has submitted its report wherein the following recommendations have been made:—

- (1) An census of actual area under rubber with special reference to mature area should be undertaken by the Rubber Board with the assistance of Revenue authorities in order to make more reliable data available.
- (2) The Rubber Boards estimate of an average yield of 294 Kg. per hectare (262 lbs per acre) in the small holdings sector is an under-estimate. It is desirable to devise more stringent measures of checking transactions by dealers to ensure not only the correct data of production but also the assessment of the cess actually due.
- (3) The existing differentials in the prices of grades of rubber should be retained as they are.

(4) For an orderly marketing of indigenous production, it is necessary that imports should come in regular monthly instalments and not as has happened during the latter half of 1966 in large quantities, just when the tapping of trees is at its height.

(5) The Rubber Board should be consulted both on the volume and programming of imports. The imports should be evenly spread out over the year.

(6) The expenses incurred by a planter for replantation should be considered as capital investment and this replantation cost must be earned through the sale of rubber. One half of the development expenses (viz., Rs. 11.67) should be included in the retention price of the grower. A new scale of subsidy is recommended to be paid to the growers to enable them to meet the cost of replantation which will not be fully recovered through the retention price.

(7) A price of Rs. 415 per 100 kgs. should be fixed as the price to be retained by the growers f.o.b. Cochin for R.M.A. 1 grade rubber. This will be exclusive of sales-tax and cess. The prices for other grades and for preserved latex will be fixed after adjustment of grade differentials indicated by the Commission.

(8) A reduction in the cess needs to be considered by Government.

(9) The rehabilitation allowance provided for replantation in Kanyakumari district of Madras State is not on a par with that in the rest of the State, and needs to be looked into by the Government of Madras.

2. Government accept recommendations (1) and (3) above.

3. Government have taken note of the recommendation (2) above.

4. Government have taken note of the recommendations (4) & (5) above and steps will be taken to implement them to the extent practicable.

5. Recommendation (6) is under examination by the Government.

6. Government have already accepted recommendation (7) in para 1 of their Resolution No. 19(15)Plant(B)/67 dated the 26th September, 1967 published in the Gazette of India Extraordinary dated the 27th September, 1967.

7. Keeping in view the expansion of the developmental and research activities of the Rubber Board for further development of the rubber plantation industry, Government do not consider it feasible to reduce the existing rate of cess on rubber, viz., 30 Paise per kg., as suggested by the Commission in recommendation (8) above.

8. Government have brought the recommendation (8) to the notice of the Government of Madras for necessary action.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. BANERJEE, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसंबर 1967

सं० 16(5)/प्लाण्ट (बी)/67. — ईरिक आयोग अधिनियम, 1951 की द्वारा 12(८) के अधीन सरकार के पर्याय मंड़ा 16(2) प्लाण्ट (बी)/65 दिनांक 28 अक्टूबर, 1960 के द्वारा ईरिक आयोग से कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने और इसकी विभिन्न श्रेणियों और किस्मों के लिए उचित मूल्य के संबंध में प्रतिवेदन दले का अनुरोध किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें निम्नलिखित विफारियों की गई हैं।

- (1) रबड़ बोर्ड द्वारा राजस्व अधिकारियों की महाया० १ में रबड़ के वास्तविक क्षेत्र, विशेषतः पूर्व विकसित क्षेत्र की गणना की जानी चाहिए ताकि अधिक विवरणीय आकड़े प्राप्त हो सकें।
- (2) रबड़ बोर्ड का प्रति हेक्टर २९४ कि०ग्रा० (प्रति एकड़ २६.२ पौड़) की औसत उपज का अनुमान कम है। यह बोर्डनीय है कि ध्यापारियों के व्यापारिक कारोबार की जांच करने के अधिक कठोर उपाय निकाले जाएँ जिनसे न केवल उत्पादन के सही आकड़े मिलना अपितु वास्तव में देय उपकर का आकलन करना भी सुनिश्चित हो सके।
- (3) रबड़ की श्रेणियों के मूल्यों में विद्यमान अंतर यथावत रखे जाने चाहिए।
- (4) स्वदेशी उत्पादन के व्यवस्थित विकास के लिए यह आवश्यक है कि आयात नियमित मासिक किस्मों में आने चाहिए न कि इस तरह जैने कि 1966 के उत्तरार्द्ध में हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा डा० समय धाई जबकि पेड़ों की चुंबाई का कार्य चरमसीमा पर था।
- (5) आयातों के फरिणाम और उनहें कर्य-अभ्य के संबंध में रबड़ बोर्ड का परामर्श लिया जाना चाहिए, आयात क्षमान मात्रा में वर्षे भर में किये जाने चाहिए।
- (6) उत्पादकों द्वारा पुनर्रॉपण पर किए गए खर्चों को पूँजीगत निवेश माना जाना चाहिए और इस पुनर्रॉपण लागत को रबड़ की विक्री में उपर्युक्त किया जाना चाहिए। विकास अर्थों का अद्वितीय (अर्थात् 11.67 रुपए) उत्पादकों के धारण मूल्य में नम्मिलित किया जाना चाहिए। उत्पादकों को दिए जाने वाले उपदान की नई दर की दिफारिश की जाती है ताकि वे पुनर्रॉपण की लागत को पूरा कर सके और धारण मूल्य के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकें।
- (7) उत्पादकों द्वारा धारण के लिए आर० एम० ए० (१) श्रेणी के रबड़ का कोकीन में जहाज तक निःशुल्क प्रति 100 किमा० 415 रुपए मूल्य नियत किया जाना चाहिए। इसमें विक्री करतथा उपकर शामिल नहीं होगा। अन्य श्रेणियों के रबड़ तथा परिरक्षित रबड़-दुर्घ के मूल्य आयोग द्वारा बताए गये श्रेणी विभेदों का दमजन करने के फलात् नियत किए जायेंगे।
- (8) सरकार द्वारा उपकर में कमी करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।
- (9) सरकार द्वारा राज्य के कन्याकुमारी जिले में पुनर्रॉपण के लिये दिया जाने वाला पुनर्स्थापन अस्ता राज्य के शेष भागों के भाग में नहीं है और इस विषय पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

2. सरकार उपर्युक्त रिफारिश (1) तथा (3) को स्वीकार करती है।
3. सरकार ने उपर्युक्त रिफारिश (2) नोट करती है।
4. सरकार ने उपर्युक्त रिफारिश (4) तथा (5) के बेख्त लिया है, प्रौर जहाँ तक व्यवहार्य दोगा उन्हें कार्यन्वित करने के लिये वक्तम उठाये जायेंगे।
5. रिफारिश (6) सरकार के विचाराधीन है।
6. सरकार ने रिफारिश (7) को भारत के अनाधारण राजपत्र (दिनांक 27 नितम्बर, 1967 में प्रकाशित अपने संकरण में लिया 19(15) 'लाण्ट (बी)')/67 दिनांक 26 नितम्बर, 1967 के वैरा 1 के द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया है।
7. रबड़ बागान रद्दोग के श्रीर विकास के लिए रबड़ बोड़ी की विकार एमक तथा गवेषणात्मक गतिविधियों के विस्तार को यज्ञ में रखते हुये सरकार रबड़ पर विद्यमान उपकर के दर, अर्थात् 30 पैसे प्रति किलो को कम करना, जैसा कि उपर्युक्त रिफारिश (8) में आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, व्यवहार्य नहीं समझती।
8. सरकार ने मद्दास रेकार का यान उपर्युक्त रिफारिश (9) की ओर आक्रायक कार्यवाही के लिये दिलाया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकरण को सभी सम्बद्धों को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकरण को वर्जनिक सूचनार्थी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम० वनर्जी

उपर्युक्त रिफारिश, भारत सरकार।